महाराष्ट्र		नासिक और नान्देड की शहरी सीमाएं
आन्ध्र प्रदेश		मानेरियल और रामागुंडम से भद्रचलम तक
महाराष्ट्र	कृष्णा	कराड से सांगली तक
महाराष्ट्र		घोम बांध से नरसरोवड़ी तक
आन्ध्र प्रदेश		सहायक नदी नीरा
आन्ध्र प्रदेश		नागार्जुन सागर बांध तक और उस बांध से रिपेला के ऊपरी भाग तक
कर्नाटक	भद्रा	उद्गम स्थान से भद्रा बांध (कर्नाटक) के के० आई० ओ० सी० एल० के निचले हिस्से तक
उड़ीसा	ब्रह्मणी	अंगुल निचला हिस्सा कामलंगा से भूबन तक
कर्नाटक	तुंगा	तीर्थ हल्ली से भद्रा के संगम तक
मध्य प्रदेश	नर्मदा	जबलपुर शहर के साथ-साथ
मध्य प्रदेश	तापी	नेपा नगर के निचले हिस्से से बरहानपुर शहर तक
उड़ीसा	बेतवा	मंडीदीप और विदिशा के साथ-साथ
हिमाचल प्रदेश	व्यास	मनाली से मंडी तक का ऊपरी हिस्सा
हिमाचल प्रदेश		मंडी के निचले हिस्से से हिमाचल प्रदेश सीमा तक
असम	कोलोंग अलोंग	नागांव शहर के साथ-साथ (असम)
असम	भोगडोई	जोरहाट शहर (असम) के साथ-साथ
असम	बड़क	सिलचर शहर (असम) के साथ-साथ
मणिपुर	इम्फाल	इम्फाल शहर (मणिपुर) के साथ-साथ
त्रिपुरा	हावड़ा	अगरतल्ला शहर (त्रिपुरा) के साथ-साथ

(ग) जी, नहीं । विशिष्ट शिकायतें मिलने पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहि:स्राव, उत्सर्जन और परिवेशी शोर मानक निर्धारित किए गए हैं;

2. उद्योगों के स्थान-निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;

3. बहि:स्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जन को निर्धारित मानकों तक सीमित रखने के लिए उद्योगों से कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की मंजूरी संबंधी अपेक्षाओं का पालन करें;

4. केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से प्रदूषक उद्योगों के अनुपालनार्थ बहि:स्राव और उत्सर्जन मानकों संबंधी एक कार्य योजना तैयार की है;

5. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा प्रदूषक उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से हटाकर अन्यत्र लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

6. परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है;

7. छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों के समूहों का सामूहिक बहि:स्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है;

8. लघु उद्योगों में प्रदूषण के निवारण के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने पर सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है;

9. जल उपस्कर में वृद्धि की गई है ताकि जल संरक्षण और उसके पुन: प्रयोग को बढ़ावा मिल सके;

10. उद्योगों में पर्यावरणीय प्रबन्धन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रदूषण निवारण के लिए उद्योगों को पुरस्कृत करने की एक योजना शुरू की गई है;

11. प्राकृतिक संसाधनों और कच्ची सामग्रियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय संपरीक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है;

12. सड़क पर चलने वाले सभी प्रकार के वाहनों के लिए मोटर-वाहन नियमावली, 1989 के तहत ठोस उत्सर्जन मानक निर्धारित किये गये हैं और ये 31 मार्च, 1990 से लागू हो गए हैं;

Pollution Control Board

3877. MISS SAROJ KHAPARDE : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to set up a Pollution Control Board for the Capital;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) The Central Pollution Control Board has delegated all the relevant powers to the Delhi Pollution Control Committee under Section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Section 6 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

This delegation of power has been notified and came into force with effect from 1st June, 1993.

(c) Does not arise.

Mishandling of Funds of Indian Embassy in Athens

3878. SHRI RAMENDRA KUMAR YADAV 'RAVI': Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Comptroller and Auditor General has objected on mishandling of funds of Indian Embassy in Athens (Greece) as reported in the "Times of India", New Delhi on 7th June, 1993 under caption 'CAG pulls up Indian Mission on funds";

(b) if so, the details thereof; and

(c) what is the reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) Yes, Sir.

(b) The details of the case are that in September 1990, the Indian Mission in Athens, with the approval of this Ministry sold government property in Athens for Greek Drachmas 80 million. Pending the permission of the Greek Government, which was mandatory, for the repatriation of funds, the Mission deposited this amount in a local bank, in a separate interest bearing Savings Bank Account. In November 1991, at the instance of the Audit authorities, the Mission learnt that no interest was being earned as foreign governments were not permitted to keep funds in any interest bearing Savings Bank Account. When this matter was reported to the Ministry, further remittances of foreign exchange from India to the Mission were stopped and the Mission was instructed to utilise these funds to meet its day-to-day requirements. From February 1992, the Mission implemented these instructions. The amount of Greek Drachmas 80 million has since been fully utilised. The objection raised by the Audit authorities was that the Mission should have settled the question of interest unambiguously before putting the funds in the Bank account.

(c) In order to avoid recurrence of such instances in future, all Indian Missions/Posts abroad have been instructed to take adequate precautions in handling public funds.

Comparision between India and USA

3879. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJI-RAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether an Indo-United Arab Emirates session of the Joint Commission for Economic Technical and Scientific Cooperation was held from June 6 to 8 this year;

(b) if so, what issues were considered at the meeting and what was the outcome thereof, and the steps taken and being taken to strengthen bilateral ties in the light thereof; and

(c) whether any extradition treaty proposals were discussed therein, if so, in what context and the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) Yes, Sir.

(b) A Press Statement issued after conclusion of the session is enclosed, which furnishes the details (*See* below).

(c) Drafts covering a possible Treaty of Juridical and Judicial Cooperation, including Extradition, have been exchanged with UAE, and India's proposal to enter into negotiations is under consideration by them.

Press Statement

The Sixth meeting of the Indo-UAE Joint Commission was held in Abu Dhabi from June 6—8, 1993.

Mr. K. Srinivasan, Secretary, Ministry of External Affairs and Mr. Mohammed Khalifa bin Yousef Al Suwaidi, Director, Economic Relations and International Cooperation,